

मौसम

अधिकतम तापमान 30.c

न्यूनतम तापमान 27.c

बाजार

सोना 98.755g

चांदी 107,000kg

सत्य का स्वर

भारत संवाद

मुंबई, प्रयागराज और लखनऊ से प्रकाशित

2

रियासी धड़कन में बढ़ाने वाला इस्तीफा, उठने लगे कई सवाल

कक्षा 10 के छात्रों के बीच बैठने को लेकर मारपीट

04

वर्ष :09

अंक :34

मुंबई , शुक्रवार , 25 जुलाई 2025

पृष्ठ : 06

मूल्य : 2: 00 रुपए

संक्षिप्त समाचार
बंगाल में बांग्लादेश सीमा के पास बीएसएफ ने 16 किलो चांदी के

आभूषण जब्त किए, एक गिरफ्तार
बीएसएफ ने कहा कि सभी 16 पैकेटों में चांदी के आभूषण पाए गए। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए सामान की कीमत लगभग 16.82 लाख रुपये है।प्रारंभिक पूछताछमें पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति बाल्टी गाँव का रहने वाला एक भारतीय नागरिक है। आगे की कानूनी कार्यवाई के लिए उसे संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने कहा है कि उसके जवानों ने दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अंतर्गत तराली सीमा चौकी पर गश्त के दौरान 16.55 किलोग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अर्धसैनिक बल ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। एक गुप्त सूचना के आधार पर, 143 बटालियन के जवानों ने एक मोटर चालित वैन को रोका और जाँच करने पर लकड़ी के वाहन के एक गुप्त स्थान में भूरे रंग के टेप में लिपटे 16 पैकेट बरामद किए। बीएसएफ ने कहा कि सभी 16 पैकेटों में चांदी के आभूषण पाए गए। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए सामान की कीमत लगभग 16.82 लाख रुपये है।प्रारंभिक पूछताछमें पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति बाल्टी गाँव का रहने वाला एक भारतीय नागरिक है। आगे की कानूनी कार्यवाई के लिए उसे संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर में अज्ञात बदमाशों ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक कार्यकर्ता की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।पुलिस अधिकारी ने बताया कि पष्ठी घोष बुधवार रात घर लौट रहे थे तभी हमलावरों ने उन्हें रोका और एक धारदार हथियार से उन पर कई बार हमला किया। उन्होंने बताया कि सड़क पर खून से लथपथ पड़े घोष को स्थानीय अस्पताल ले जाया गयाजहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि आशंका है कि संपत्ति के मामलों को लेकर आपसी रंजिश के कारण यह हत्या की गई हो, लेकिन असली मकसद जांच के बाद ही पता चलेगा। आरोपियों की तलाश जारी है। इस बीच, मृतक के परिवार ने दावा किया कि घोष की हत्या तृणमूल कांग्रेस से जुड़े होने के कारण की गई।पुलिस ने बताया कि एक अन्य घटना में दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप इलाके के मधुसूदनपुर में बुधवार को एक पंचायत सदस्य के भतीजे की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि घर से निकलने के कुछ समय बाद युवक का शव एक खुले मैदान में मिला।

राजनीति गुलाम नबी आजाद बोले - राजनीति अस्थायी है, लेकिन हम...

'हमारे बीच जो भाईचारा था वह अब खत्म हो रहा है'

एजेंसी नयी दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और 'डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी' (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को खत्म होते भाईचारे पर चिंता व्यक्त की और सभी के राजनीतिक विचारों से परे सभी का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आजाद रियासी ज़िले में एक पार्टी कार्यक्रम के पिता के निधन पर संवेदना व्यक्त करने आए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, रमेशा हमेशा से मानना रहा है कि आप जिसे भी जानते हैं, चाहे उसका धर्म या पार्टी कुछ भी हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। राजनीति अस्थायी है, लेकिन हम पहले इंसाan हैं। चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों या किसी भी पार्टी से हों, जम्मू-कश्मीर में



जो भाईचारा पहले था, वह अब खत्म हो रहा है। र विभाजनकारी राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करते हुए, आजाद ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से एकजुट होकर शांति, सम्मान और सहयोग पर आधारित सामाजिक ताने-बाने का पुनर्निर्माण करने का आग्रह किया। सामूहिक प्रयास से ही यह क्षेत्र स्थिरता और विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। अपने दौरे के दौरान,

आजाद ने निवासियों की चिंताओं को भी धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों को उचित मंचों पर उठाया जाएगा। उनके साथ रियासी जिले के कई वरिष्ठ पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी माँग भी दोहराई और तर्क दिया कि यह क्षेत्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। आजाद ने कहा

आजाद ने कहा कि विकास के लिए, राज्य में प्रगति के लिए, राज्य का दर्जा आवश्यक है। और राज्य का दर्जा कोई हिंदू-मुस्लिम मुद्दा नहीं है, न ही केवल कश्मीरी मुद्दा है। यह हर पार्टी, हर धर्म, हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। चाहे कोई जम्मू में भाजपा से हो या कश्मीर में नेशनल कॉन्फेंस से, या कांग्रेस या पीडीपी से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान - राज्य का दर्जा सभी के लिए आवश्यक है। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ रजम्मू-कश्मीर के लोगों को थोखा देने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद क्षेत्र का

राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को पूरा नहीं करने का विरोध किया। कांग्रेस नेता और पार्टी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए कहा कि केंद्र क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने के वादे के बाद अपने वादे से मुकर रहा है। वेणुगोपाल ने पार्टी कार्यक्रमों की नारेबाजी के बीच कहा कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को थोखा दे रही है। उन्होंने पहले ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, जिसे वे पूरा नहीं कर रहे हैं।

भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

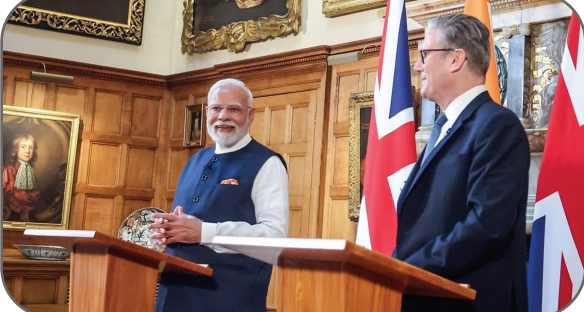
प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टार्मर की मौजूदगी में साइन हुए, 99% भारतीय सामान ब्रिटेन में टैक्स फ्री

एफटीए के प्रमुख आयाम और चुनौतियों देखें तो इसके जरिए भारत को ब्रिटेन के वस्त्र, दवा, आईटी, ऑटो पार्ट्स और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी, वहीं ब्रिटेन के लिए भारतीय शिक्षा, कानूनी सेवाओं और शराब के क्षेत्र में प्रवेश के नए अवसर खुलेंगे।

एजेंसी

भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मौजूदगी में गुरुवार को लंदन में एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इसे लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। समझौते के बाद नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताया है खुशी जताई। उन्होंने भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। मोदी ने स्टार्मर को भारत आने का न्योता दिया।

ब्रेकिंग के बाद ब्रिटेन का यह



भारत के 99% निर्यात को टैरिफ में राहत मिलेगी
इस समझौते से भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ यानी आयात शुल्क में राहत मिलेगी। इसका मतलब है कि भारत से जो सामान ब्रिटेन भेजा जाएगा, उस पर लगने वाला टैक्स या तो बहुत कम हो जाएगा या पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। वहीं, ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भी यह समझौता फायदेमंद होगा।

सबसे बड़ा व्यापार समझौता
यूरोपियन यूनियन से अलग होने (ब्रेकिंग) के बाद ब्रिटेन का यह सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच ट्रेड में 34 बिलियन डॉलर की वृद्धि होने का अनुमान है। इससे पहले ब्रिटेन का सबसे बड़ा समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ 2020 में हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार में 3.1 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। ब्रेकिंग के ब्रिटेन ने अब तक 70 से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड डील की है। अब उन्हें भारत में व्हिस्की, कार और दूसरे उत्पाद बेचने में पहले से ज्यादा आसानी होगी। भारत इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को घटाकर 15% से 3% करेगा। समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है।

देश को 23 साल बाद मिली नई सहकारिता नीति

अमित शाह बोले - 2047 तक भारत बनेगा विकसित

एजेंसी अमित शाह ने कहा कि आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति - 2025 का शुभारंभ हुआ है। 2002 में, भारत सरकार ने सहकारिता नीति पेश की थी। उस समय भाजपा सरकार थी। और आज, 2025 में, भाजपा सरकार द्वारा दूसरी सहकारिता नीति लाई गई है। करने के केंद्र के उद्देश्य का हिस्सा है और 2025-45 तक यानी अगले दो दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में एक मोल का पत्थर साबित होगी। अमित शाह ने कहा कि आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का शुभारंभ हुआ है।

हंगामे के भेंट चढ़ा मानसून सत्र का चौथा दिन

आपको बता दें कि विपक्ष ने केंद्र सरकार पर एसआईआर अभ्यास, ऑपरेशन सिंदूर, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर बातचीत करने के डोनाल्ड ट्रम्प के बार-बार दावों पर बहस के लिए दबाव बनाना जारी रखा है, साथ ही सत्र के पहले दिन के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अवानक इस्तीफे पर जवाब मांग रहा है।

लोकसभा की कार्यवाही
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का अनावरण किया, जो पिछले 23 वर्षों से लागू एक नीति का स्थान लेगी। यह उस विभाग के लिए एक और मोल का पत्थर साबित होगी जिसकी भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लगातार बढ़ रही है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, नई नीति देश में सहकारिता को मजबूत

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरेला ने बृहस्पतिवार को सदन में हंगामा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों को आड़े-हाथों लिया और कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के संसकार सदन में नारेबाजी करने, तख्तियां लाने और मेजेंटीकने के लिए नहीं रहे हैं, लेकिन इस दल के मौजूदा सांसदों का आवरण पूरा देश देख रहा है। एजेंसी मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। सदन में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र शुरू होने से पहले, विपक्षी सदस्यों ने बिहार के लोगों को थोखा देने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित अन्य मुद्दों को लेकर संसद के मकर

2002 में, भारत सरकार ने सहकारिता नीति पेश की थी। उस समय भाजपा की सरकार थी। और आज, 2025 में, भाजपा सरकार द्वारा दूसरी सहकारिता नीति लाई गई है। करने के केंद्र के उद्देश्य का हिस्सा है और 2025-45 तक यानी अगले दो दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में एक मोल का पत्थर साबित होगी। अमित शाह ने कहा कि आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का शुभारंभ हुआ है।

50 मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ आरएसएस चीफ की अहम बैठक

कितनी कारगर होगी मोहन भागवत की पहल?
आरएसएस, अपने संबद्ध संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के माध्यम से मुस्लिम मौलवियों, विद्वानों और समुदाय की प्रमुख हस्तियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। 2023 में, एमआरएम ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ने और एक वाद, एक ध्वज, एक राष्ट्रगान की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना की घोषणा की है। एजेंसी सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की एक उल्लेखनीय पहल के तहत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय

हष्टिकोण, जो भारत को, उसके विकास को, और भारत के विकास के लिए आवश्यक सभी कारकों को समझता है, वहीं सहकारी क्षेत्र को महत्व दे सकता है... यदि देश और अर्थव्यवस्था की मूल इकाई समृद्ध, रोजगारयुक्त और संतुष्ट है, तो वह आर्थिक मॉडल कभी विफल नहीं हो सकता। शाह ने जोर देकर कहा कि सहकारिता नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि नीति का केंद्रबिंदु लोग, गाँव, कृषि, गाँव की महिलाएँ, दलित, आदिवासी हों।

पर्दे के पीछे जरूर कुछ हुआ है, उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर बोले सचिन पायलट



एजेंसी नयी दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी महासचिव सचिन पायलट ने गुरुवार को जगदीप धनखड़ के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। टोंक में पत्रकारों से बात करते हुए पायलट ने कहा कि

पायलट ने इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसी स्थिति में औपचारिक विवाद आम बात है। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे निश्चित रूप से कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण उन्हें अप्रत्याशित इस्तीफा देना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के नेतृत्व में 'भ्रष्टाचार विरोधी' पदयात्रा के बारे में पायलट ने कहा कि सभी को अपने अधिकारों की वकालत करने का अधिकार है।

इस्तीफा देना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के नेतृत्व में 'भ्रष्टाचार विरोधी' पदयात्रा के बारे में पायलट ने कहा कि सभी को अपने अधिकारों की वकालत करने का अधिकार है। मीणा ने पिछले साल टोंक जिले के देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा था और एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को थपड़ मारने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन पहले ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी थी।



सम्पादकीय

स्वच्छ ऊर्जा में विश्व को राह दिखाता भारत, जल्द हासिल होंगे बड़े लक्ष्य

नवीकरणीय ऊर्जा पर अंतरराष्ट्रीय नीति में भी बदलाव जरूरी है। इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने से लेकर तकनीकी हस्तांतरण की नीति न केवल उदार बनानी होगी बल्कि कई जटिल पहलुओं का भी ध्यान रखना होगा। भारत की सफलता इस मामले में उम्मीद जगाती है। यदि भारत यह लक्ष्य हासिल कर सकता है तो दुनिया भी उस दिशा में आगे बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन की निरंतर विकराल होती चुनौती के बीच स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाने को लेकर कोई दुविधा नहीं। इसके बावजूद यह चर्चा जीवाश्म ईंधन और रीन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर अनावश्यक द्वंद्वों में फंसी है। इसमें ऊर्जा परिदृश्य पर संक्रमण की जटिलता को अनदेखा किया जा रहा है और यह स्थिति ग्लोबल साउथ यानी विकासशील या उभरती हुई अर्धव्यवस्था में अधिक देखने को मिल रही है। आवश्यकता जीवाश्म ईंधनों को पूरी तरह से त्यागने की नहीं, बल्कि उन पर निर्भरता घटाने की एक संतुलित नीति एवं गैर-जीवाश्म ईंधनों में रणनीतिक निवेश बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने की है। सौर, पवन, जल, परमाणु और जैव ऊर्जा में निवेश इस रणनीति के मूल में होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि बीते एक दशक में सौर एवं पवन ऊर्जा की लागत 80 प्रतिशत से भी अधिक घट गई है। इसके चलते कई क्षेत्रों में सौर-पवन ऊर्जा की लागत कोयले और गैस से बनने वाली बिजली से भी किफायती हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा कीमतों में स्थायित्व प्रदान करने के साथ ही ऊर्जा स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करती है। एक बार इंस्टाल होने के बाद उसमें लागत लगभग नगण्य रह जाती है। ये कुछ ऐसे लाभ हैं जिनकी जीवाश्म ईंधन कभी बराबरी कर ही नहीं सकते। ऐसी क्षमताओं से भू-राजनीतिक गतिरोधों से भी सहजतापूर्वक निपटा जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों में तनाव भड़कने से आपूर्ति भ्रंशला प्रभावित हो जाती है। रूस-यूक्रेन युद्ध इसका बड़ा उदाहरण रहा। स्वच्छ घरेलू ऊर्जा में निवेश करने वाले देश ऐसी अस्थिरता से बचे रह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना इसलिए और अनिवार्य हो गया है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अकेले जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी करीब तीन-चौथाई है। स्पष्ट है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर दांव लगाए बिना कार्बन से पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा। इतने व्यापक लाभ के बावजूद यह एक तथ्य है कि विकसित देश भी स्वच्छ ऊर्जा के अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं। शुरुआती स्तर पर बढ़त हासिल करने के बाद यूरोपीय संघ के कदम भी इस मोर्चे पर ठिठक गए। इसमें राजनीतिक दबाव, कीमतों को लेकर चिंता और कार्बन नियमनों को लेकर बढ़ते विरोध जैसे पहलू प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

आज का विचार

चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें चरित्र को नष्ट करती हैं

भारत संवाद



मेघ राशि: करियर: परोपकार में मन लगेगा, लेकिन खुद का काम प्रभावित हो सकता है। बिजनेस: विरोधियों से सावधान रहें, रुकावटें आ सकती हैं। धन: पुराना लेनदेन समय पर न चुकाने पर परेशानी होगी। शिष्य: ध्यान बंट सकता है, फोकस बनाए रखें। लव/पारिवारिक: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

वृषभ राशि: करियर: कार्यस्थल का माहौल सहयोगात्मक रहेगा। बिजनेस: मेहमानों के आगमन से वातावरण प्रसन्न रहेगा। धन: खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। शिक्षा: स्वास्थ्य में सुधार के साथ पढ़ाई में ध्यान लगेगा। शिष्या: शिक्षण से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है।

वृश्चिक राशि: करियर: आय में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बिजनेस: प्रभावशाली लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। शिक्षा: शिक्षण से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है।

धनु राशि: करियर: कानूनी मामलों में जीत के योग हैं। बिजनेस: घरेलू वस्तुओं पर खर्च संभव है। धन: विरोधियों से सतर्क रहें, आर्थिक नुकसान से बचें। शिक्षा: मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। लव/पारिवारिक: मतभेद हो सकते हैं, धैर्य से काम लें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मकर राशि: करियर: जिम्मेदारियां पूरी होंगी, कार्य में सफलता मिलेगी। बिजनेस: प्रॉपर्टी से लाभ संभव है। धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। शिक्षा: एकाग्रता बनी रहेगी, रिजल्ट अच्छे आएंगे। लव/पारिवारिक: मांगलिक कार्य के योग हैं, पारिवारिक आनंद रहेगा। उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ राशि: करियर: स्वास्थ्य कारणों से व्यस्तता बनी रहेगी। बिजनेस: संपत्ति के लेन-देन में सावधानी रखें। बजट गड़बड़ा सकता है, खर्चें संभालें। शिक्षा: पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें।

मीन राशि: करियर: अटक हुई डील फाइनल हो सकती है। बिजनेस: योजनाएं सफल होंगी, लाभ के योग हैं। धन: महत्वपूर्ण सूचना से आर्थिक लाभ संभव। शिक्षा: छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।

ज्योतिष सेवा केन्द्र
ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री

सियासी धड़कनें बढ़ाने वाला इस्तीफा, उठने लगे कई सवाल



दो साल पहले जब धनखड़ उपराष्ट्रपति बने तब कहा गया था कि भाजपा नाराज किसानों खासकर जाट समुदाय को साधना चाहती है। वह चुनावी हित कितना सधा इसका विश्लेषण भाजपा ने अवश्य किया होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि धनखड़ की नई भूमिका क्या होगी और नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इसे लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से भी ज्यादा

आश्चर्यजनक उनका इस्तीफा है। यह दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद न तो यूं ही किसी को मिल जाता है और न ही कोई इसे ऐसे ही छोड़ देता है। जनता दल से राजनीति शुरू कर कांग्रेस के रास्ते भाजपा में आए धनखड़ का पहले राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बनना चौंकाने वाला रहा। उन्होंने मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा का कारण स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बताया, लेकिन इसे लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफे की बात लोगों के गले नहीं उतर रही तो उसका कारण नेताओं का पद-मोह भी है। पद तो दूर, स्वेच्छ से राजनीति छोड़ने वाले नेता देश में ज्यादा नहीं हुए। वैसे इसी मार्च में एंजियोप्लास्टी के बाद भी धनखड़ की मुखरता में कोई कमी नहीं आई। चाहे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी बरामदगी का मामला हो या राज्य सरकारों के विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समयसीमा का निर्धारण, हर मुद्दे पर वे खुल कर बोले। संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान जोड़े गए समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग तथा एक देश-एक चुनाव जैसे राजनीतिक मुद्दों पर भी वे मौन नहीं रहे। धनखड़ के ऐसे बयानों को विपक्षी दलों ने सरकार



और भाजपा के एजेंडे से जोड़कर देखा और दिखाया। धनखड़ सबसे मुखर और शायद विवादास्पद उपराष्ट्रपति रहे। बीच कार्यकाल में संसद सत्र के दौरान इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति के साथ ऐसे राज्यसभा सभापति भी हैं, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हुई। पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध पिछले साल दिसंबर में अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में लगा विपक्ष ही अब उनका गुणगान करते हुए सरकार से सवाल कर रहा है। यह राजनीति का अवसरवादी चरित्र ही है। ऐसे मुखर व्यक्ति के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठना स्वाभाविक है, पर सच प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और खुद जगदीप धनखड़ के अलावा शायद ही कोई जानता हो। विपक्षी खेमे से दो परस्पर विरोधी कहानियों को हवा दी जा रही है। पहली, बिहार को साधने के लिए एक तीर से दो निशाने

लगाए गए हैं, नीतीश कुमार को अगला उपराष्ट्रपति बना कर बिहारी अस्मिता के नाम पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बिहार में पहला भाजपाई मुख्यमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। दूसरी, मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू के व्यवहार से आहत होकर धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। यह भी कहा जा रहा कि सोमवार दोपहर बाद हुई कार्य मंत्रणा समिति की दूसरी बैठक में नट्टा और रिजीजू के न आने से धनखड़ खफा हुए। उपराष्ट्रपति होने के नाते वह राज्यसभा के सभापति भी थे और सदन के संरक्षक भी। सदन की कार्यवाही में क्या दर्ज होगा और क्या नहीं, यह तय करना उन्हीं का विशेषाधिकार है। उनके आसन पर आसीन होते हुए भी नट्टा ने जिस अंदाज में विपक्ष को चेताया, उससे शायद धनखड़ ने खुद को

आहत महसूस किया। नट्टा ने कहा था कि उनका बोला रिकार्ड में नहीं जाएगा। एक और कहानी धनखड़ द्वारा जस्टिस वर्मा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को सरकार से चर्चा किए बिना ही मंजूरी की भी चल रही है। वैसे तो संवेदनाओं के आहत होने का कोई नियत पैमाना नहीं, पर जगदीप धनखड़ की छवि आवेश में फैसले लेने वाले नेता की नहीं रही, वरना जनता दल से सांसद और फिर कांग्रेस से विधायक रहने के बाद भाजपा में आकर उपराष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंच पाते। तब क्या धनखड़ के इस्तीफे के पीछे वाकई कोई सुनियोजित रणनीति है? भाजपा की राजनीतिक शैली को देखें तो वहां अनायास ही कुछ नहीं होता। भाजपा अन्य दल से आए नेताओं को आसानी से महत्वपूर्ण पद नहीं देती। इस मामले में हिंमत विस्वा सरमा, सत्यपाल मलिक और धनखड़ सरीखे कम ही अपवाद हैं। पूर्वोत्तर में भाजपा के प्रसार में

भूमिका के पुरस्कार स्वरूप पूर्व कांग्रेसी हिमंता अब असम के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में धनखड़ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टकराव लगातार सुर्खियों में रहा। उपराष्ट्रपति बनाए जाने को विपक्ष उसी से जोड़कर देखता है, पर इनमें सत्यपाल मलिक ने भाजपा की साख को जितना नुकसान पहुंचाया, उतना तो विरोधी भी नहीं पहुंचा सके। दो साल पहले जब धनखड़ उपराष्ट्रपति बने, तब कहा गया था कि भाजपा नाराज किसानों, खासकर जाट समुदाय को साधना चाहती है। वह चुनावी हित कितना सधा, इसका विश्लेषण भाजपा ने अवश्य किया होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि धनखड़ की नई भूमिका क्या होगी और नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इसे लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। यदि उपराष्ट्रपति पद के जरिये चुनावी बिसात ही बिछानी होगी, तो भाजपा दक्षिण भारत के अपने किसी नेता की ताजपोशी चाहेगी, जहां उसकी सत्ता का एकमात्र दुर्ग कर्नाटक भी ढह चुका है। भाजपा की राजनीति, रणनीति और प्रबंधन को अतीत के अनुभव से समझने की कोशिश करें तो निकट भविष्य में कई बड़े परिवर्तन होने हैं। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का अर्से से इंतजार है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि संगठन से लेकर मंत्रिमंडल और सत्ता-प्रतिष्ठान में बड़े बदलाव देखने को मिलें।

मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों का फैसला और उठते सवाल

ललित गर्ग

11 जुलाई 2006 को मुंबई की भीड़भरी लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया था। पीड़ित परिवारों के साथ-साथ जन-जन को आहत किया था। 7 जगहों पर हुए इन धमाकों में 187 निर्दोष लोगों की जान गई और 824 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। लेकिन इन बम धमाके को लेकर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कोर्ट ने विशेष मकोका अदालत की ओर से 12 अभियुक्तों को दी गई सजा को गैरकानूनी करार दिया। इन सभी आरोपियों का बरी हो जाना सवाल के साथ-साथ चिन्ता भी पैदा करता है। इसीलिये करीब 19 साल बाद आए अदालत के इस फैसले को लेकर न केवल कानूनी दायरे में, बल्कि सामाजिक व नैतिक दृष्टिकोण से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल वहीं घूमकर आ जाता है कि इतने बड़े नुकसान का दोषी कौन है?

लम्बी न्यायिक प्रक्रिया एवं जांच के बाद 2015 में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया, जिसमें से 5 को फांसी और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला लगभग 8 वर्षों की सुनवाई, 250 से ज्यादा गवाहों और हजारों पन्नों की गवाही के बाद आया। लेकिन 2023 और फिर 2025 में कुछ सिविल सोसाइटी संगठनों, मानवाधिकार समूहों और कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ दोषियों को पर्याप्त सबूतों के बिना फंसाया गया, पुलिस की जांच पक्षपातपूर्ण रही और कई जगह कानून के दायरे का अतिक्रमण किया गया। इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में जिस तरह से एक-एक करके सारे सबूतों की ध्वजियां उड़ायी, उससे पूरे सिस्टम को लेकर संदेह उठता है। जब इतने अहम मामले में इतनी लचर एवं लापरवाहीपूर्ण जांच



हुई, तो फिर दूसरे तमाम केस में क्या होता होगा? गवाहों के बयान दर्ज करने से लेकर सबूत जुटाने तक, हर जगह लापरवाही एवं कोताही बरती गई।

कानून की दृष्टि में अपराध केवल घटना नहीं, उस घटना के पीछे की मंशा, सबूतों की पुष्टि, प्रक्रिया की शुद्धता और निष्पक्षता की भी मूल्यांकन करता है। हृदोषी को सजा मिलनी चाहिए-यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, लेकिन ह्विनदोष को दंड न मिले-यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है। भारतीय दंड संहिता, मकोका और गैरकानूनी गतिविधियों से रोकथाम अधिनियम (यूपीए) जैसे सख्त कानून आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए, लेकिन इनका उपयोग अक्सर राजनीतिक प्रभाव, मीडिया ट्रायल, या जनभावनाओं को शांत करने के लिए किया गया है। ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में अनेक ज्वलंत सवाल खड़े हुए हैं कि क्या सभी दोषियों को वास्तव में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर दोषी ठहराया गया है? यदि नहीं, तो यह न्याय व्यवस्था के लिए एक गंभीर प्रश्न है। क्या पुलिस या जांच एजेंसियों ने निष्पक्ष जांच की? कई बार जांच एजेंसियों पर ह्वनतीजे पहले, जांच बाद में हूँ का आरोप लगा है। क्या विशेष अदालतों का गठन निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है या त्वरित दंड की नीति अपनाता है? क्या कानून केवल सख्ती का पर्याय बन गया है या उसमें मानवीय संवेदना का स्थान है? क्या मीडिया ट्रायल ने वास्तविक न्याय को प्रभावित किया? इन प्रश्नों के उत्तर मिलना ही चाहिए दिश के सामने

गंभीर चुनौती है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें निचली अदालतों में दिये गये मौत की सजा को ऊपरी अदालतों ने बदल दिया। जांच में खामियों, गवाहों में कमी और कमजोर सबूतों के चलते ऊपर की अदालतों में केस खारिज होते हुए बार-बार देखे गये हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक आरोपी की मौत की सजा को खारिज करते हुए कहा कि हजब दांव पर इंसानी जिंदगी लगी हो और उसकी कीमत खून हो, तो मामले को पूरी इमानदारी से देखा जाना चाहिए। हूँ दुर्भाग्य से मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट की जांच में इस भावना का सही से पालन नहीं किया गया। इस मामले में सभी आरोपियों का बरी हो जाना न केवल न्याय प्रक्रिया पर बल्कि जांच एजेंसियों पर सवाल पैदा करता है। प्रश्न है कि अगर 12 लोग निर्दोष थे तो इतने बरसों तक आतंकी होने का दाग लिए जिल्लत की जिंदगी क्यों जीते रहे? अगर ये दोषी थे तो जांच इतनी कमजोर क्यों हुई? यह केस निचली अदालतों के कामकाज के तरीकों पर भी बड़ा सवालिया निशान है। सबूतों को लेकर इतने संदेह थे, लेकिन निचली अदालत ने उन पर गौर नहीं किया। यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी न्याय प्रक्रिया की विसंगति ही है। यह पहला मामला नहीं, जहां जांच में खामियों, गवाही में कमी और कमजोर सबूतों के चलते ऊपर की अदालतों में केस खारिज हो गया हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते तीन लोगों की मौत की सजा रद्द करते हुए उन्हें हत्या आरोपों से बरी कर दिया था। पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने भी 2011 में हुई दोहरी हत्या और रेप के आरोपी को छोड़ने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने जांच में गंभीर कमियां गिनाई थीं। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि झूठे मुकदमों को वजह से जिन्हें लंबा समय जेल में बिताना पड़ा है, उन्हें मुआवजा देने के लिए कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। अब मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

विकास की अवधारणा और अशिक्षा और अंधविश्वास

संजीव ठाकुर

आश्चर्य की बात है कि आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी से शिक्षित जनमानस भी अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का अंधभक्त और अनुयाई हो गया है। अंधविश्वास का आलम भारत में नहीं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, इसराइल और तमाम अन्य यूरोपीय देशों में व्याप्त है। अमेरिका तथा ब्रिटेन में 13 नंबर को अत्यंत अशुभ माना जाता है। भारत में यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो व्यक्ति उस तरफ न जाकर दूसरे रास्ते से जाना पसंद करता है। मकान में वास्तु दोष दूर करने के लिए अनावश्यक तोड़फोड़ और सुधार के लिए लाखों खर्च किए जाते हैं। यह अंधविश्वास का एक जीता जागत प्रमाण है। वास्तु दोष तथा अंधविश्वास को मानने वाले 90% शिक्षित युवा इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। अशिक्षा और अज्ञानता ने अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता को भारत में फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है हूँ यदि अशिक्षित मनुष्य धार्मिक अंधविश्वास को मानता है तो यह बात कुछ थोड़ी देर के लिए समझ में आती है किंतु इस वैज्ञानिक युग में अत्यंत शिक्षित एवं पढ़े-लिखे लोग भी अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता के पीछे भागने लगे तो यह समाज और देश के लिए दुर्भाग्य की बात है हूँ यह तो तय है कि शिक्षा, ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर के विवेकपूर्ण विचारों को सोचने की शक्ति प्रदान करता है और इसके पश्चात ही मनुष्य वैज्ञानिक आधार पर तर्क-रखकर अपनी बात को मानना शुरू करता है। पूर्व में हम मानते थे कि पृथ्वी चपटी है किंतु वैज्ञानिक प्रयोगों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल है अब लोगों ने लॉजिक और वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर यह मान लिया है की पृथ्वी गोल ही है शहीद भगत सिंह ने आजादी के

लिए एक संगठन नौजवान भारत सभा का गठन किया और उसके घोषणा पत्र में कहा था कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता हमारी प्रगति के बहुत बड़े बाधक है, वह हमारे रास्ते की बाधा साबित हुए हैं उनसे हमें हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहिए जो पद्धति आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए इसी प्रकार अन्य बहुत सारी कमजोरियां भी हैं जिन पर हमें विजय प्राप्त करना होगा ,इस कार्य के लिए सभी समुदाय को क्रांतिकारी उत्साह रखने वाले नई सोच के नौजवानों की आवश्यकता है हूँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा था क्योंकि युवा शक्ति ही देश में नए विचारों की क्रांति ला सकता है और अंधविश्वास से भी है विज्ञान ने अनेक अंधविश्वास को जन सूचियों में अविश्वास के रूप में में स्थापित किया है और शिक्षा तथा विज्ञान तकनीकी ऐसे मार्ग हैं जिन से चलकर हम न सिर्फ चांद पर पहुंचे हैं बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरी दुनिया एक परिवार की तरह एक दूसरे के एकदम करीब आ चुकी है ऐसे में अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता एवं संप्रदायवाद की जगह कहीं बच जाती है भला ? शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो जाना चाहिए की इन अंधविश्वासी बातों और मिथकों का अस्तित्व ही मूल रूप से विस्मृत किया जाना चाहिए हूँ बिल्ली के रास्ता काटने से काम रुक जाता है, किसी की छोँक देने से अशुभ संकेत स्थापित होने लगते हैं यदि कैंवा बोलता है तो मेहमान आने का संकेत माना जाना इन सब बातों की कोई तार्किक अथवा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि नहीं है

छहफीट तक ऊंची मूर्तियों का कृत्रिम जलाशयों में

विसर्जन...गणेशोत्सव से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के आगम से पहले बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि 6 फीट तक की ऊंचाई रखने वाली मूर्तियों को कृत्रिम जलाशयों में ही विसर्जन के लिए ले जाया जाए। कोर्ट ने सरकार को भी निर्देश जारी किए हैं।



204 जल कुंड बनाए हैं। एक अनुमान के अनुसार इनमें करीब 85 हजार मूर्तियों का विसर्जन हो पाएगा। ऐसे में देखना होगा कि बाकी मूर्तियां कहाँ पर विसर्जन के लिए ले जाई जाएंगी। 127 अगस्त से विराजेंगे बप्पाबॉम्बे हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा उत्सव की मूर्तियों के विसर्जन को लेकर सुनवाई करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि मूर्तियों के विसर्जन का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। अदालत ने आगे कहा कि इसलिए 6 फीट ऊंची मूर्तियों का विसर्जन अनिवार्य रूप से कृत्रिम जलाशयों में ही किया जाना चाहिए।

वसई-विरार में छह महीनों में २१ हत्याएं और ३३ जानलेवा हमले

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

वसई-विरार और मीरा-भायंदर क्षेत्र में हिंसा की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। जनवरी २०२५ से जून २०२५ तक के छह महीनों में पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में २१ हत्या के मामले सामने आए हैं, जबकि ३३ लोगों पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। बॉम्बा और हत्या के प्रयासों की ये घटनाएं चौंकाते वाली इसीलिए हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर मामले नशे, गुस्से, प्रेम संबंध, पैसों के लेन-देन या पुरानी दुश्मनी जैसे कारणों से जुड़ी हैं। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी और फरवरी में ३-३ मार्च में सबसे ज्यादा ७ अप्रैल और जून में ४-४ हत्याएं दर्ज हुईं, जबकि मई में कोई हत्या नहीं हुई। गंभीर अपराधों की बात करें तो हर महीने औसतन ५ से ७ ऐसे मामले सामने आए, जिनमें चाकू से हमला, अपहरण या बलात्कार जैसे अपराध शामिल हैं। पुलिस ने सभी हत्या के मामलों को सुलझा लिया है, लेकिन अपराध की वजहों पर गौर करें तो तस्वीर और भी खतरनाक नजर आती है। इन घटनाओं में कई बार

वजह इतनी मामूली होती है कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों के बीच बहस, शराब पार्टी में झगड़ा, वाहन टकरा जाने पर गुस्सा या फिर सिर्फ धूरकर देखने जैसी बातों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। कई मामलों में आरोपी और पीड़ित पहले एक-दूसरे के दोस्त रहे हैं। एक केस में तो बर्थेंड पार्टी के दौरान नशे में हुए झगड़े के बाद युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना पापडी इलाके की है, जहां लोहिया नगर में रहने वाले आकाश पवार की उसके दोस्त मनीष पांडे ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पार्टी में शराब के नशे में हुई बहस के बाद मनीष ने आकाश और राहुल भुरकुड पर हमला कर दिया था। आकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि राहुल गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती हिंसक प्रवृत्तियों के पीछे गुस्से पर नियंत्रण न होना एक बड़ा कारण है। कई बार लोग गुस्से में इतना बह जाते हैं कि छोटी-सी बात पर चाकू तक निकाल लेते हैं। इसलिए समाज में मानसिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग और गुस्से को

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के दोषियों को रिहा करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों को निर्दोष न माना जाए।

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 11 जुलाई 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो दोषी जेल से रिहा हुए हैं, उन्हें फिलहाल जेल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें निर्दोष न माना



जाए। [सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से के तहत चल रहे दूसरे मामलों पर असर पड़ेगा।] सरकारी वकील को दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने

थे। इन धमाकों में 209 लोगों की मौत हो गई थी। 1800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। कोर्ट ने जिन 11 दोषियों को निर्दोष बताया है, उनमें से 4 नागपुर जेल में बंद हैं। इसके अलावा 4 अमरावती जेल में थे। नागपुर जेल में बंद एक आरोपी की मौत हो चुकी है। दो आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। एक आरोपी अभी भी जेल में है, क्योंकि उस पर एक और केस चल रहा है।

दहल गई थी मुंबई

2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में जो बम धमाके हुए थे, वे बहुत ही भयानक थे। इन धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना से पूरा मुंबई शहर दहल गया था। इस बम धमाके की जांच एनआईए ने की थी।

पत्नी ने डिनर में चिकन और चाइनीज नहीं बनाया तो पति बना हैवान, जान लेने की कोशिश

मुंबई में बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मुंबई के ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा खाने में चिकन और चाइनीज नहीं परोसने पर शख्स ने पत्नी पर हमला बोला दिया। पत्नी ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। पुलिस पूरी घटना की सभी एंगल से जांच कर रही है।

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मुंबई: मुंबई के ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा में एक आदमी ने डिनर में पेट भर चिकन और चाइनीज नहीं मिलने पर अपना आधा खो दिया। आरोप है कि इस नाराज पति को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी से मारपीट की। फिर सिर पर रॉड से हमला कर दिया। हमले में उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, फिलहाल वह खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस इसे दहेज उत्पीड़न का मामला मान रही है।

किसी तरह से बच गई पत्नी

पुलिस के मुताबिक यह दिल दहला देने वाली घटना 3 जुलाई को ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा में हुई। 38 साल का अजन अरुण डभाडे परिवार के साथ डिनर कर रहा था। इस दौरान उसने अपनी पत्नी स्वाति से एक्स्ट्रा चिकन और चाइनीज की डिमांड की। स्वाति ने उसे बताया कि वह और नहीं परोस सकती क्योंकि खाना खत्म हो गया। इतना सुनते ही अजन बड़क गया। आरोप है कि उसने लोहे की रॉड से स्वाति के सिर पर वार कर दिया। हमले के बाद खून से लथपथ स्वाति को तुरंत शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका इलाज



किया गया। ठीक होने के बाद स्वाति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अजय डभाडे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

दहेज का भी दर्ज कराया था केस

मुंबई पुलिस ने अजय की मां को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे अजय को मारपीट के लिए उकसाया था। पुलिस की शुरूआती जांच में यह भी पता चला है कि स्वाति ने एक जून को अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। उसका पति अजय डभाडे उस पर केस वापस लेने का प्रेशर बना रहा था। स्वाति ने आरोप लगाया है कि डभाडे उससे इसलिए भी नाराज था क्योंकि उसने अपने पिता के घर से 5 लाख रुपये लाने से इनकार कर दिया था, ताकि वह अपना मनी-लैंडिंग का कारोबार चला सके। पुलिस का कहना है कि वह इस केस में सभी एंगल से जांच कर रही है।

नांदेड बस स्टॉप में एमनसएस वकर्स ने हिंदी भाषी को पीटा, मराठी न बोलने पर पैर पड़वाए, फिर राज ठाकरे से मंगवाई माफी

नांदेड में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक हिंदी भाषी व्यक्ति को पीटा, क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की। बस स्टॉप पर बने शौचालय के कर्मचारी से बहस हुई थी। उस व्यक्ति ने महिलाओं से शौचालय इस्तेमाल करने के लिए पैस लेने का आरोप लगाया था। बहस के बाद, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी को थप्पड़ मारे और माफी मांगने को कहा।

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

नांदेड : महाराष्ट्र में एमनसएस कार्यकर्ताओं ने फिर एक हिंदी भाषी शख्स को पिटाई की है। उन्होंने उसे इसलिए पीटा क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की। उसने कहा कि मैं इस भाषा में बात नहीं करूंगा। तुम क्या करोगे ? इस घटना की सीरीज के कई वीडियो सामने आए हैं। इसमें दिख रहा है कि एक आदमी नांदेड के बस स्टॉप पर बने पब्लिक टॉयलेट के कर्मचारी से सवाल कर रहा है। वह आरोप लगा रहा है कि महिलाओं से टॉयलेट



आदमी के बगल में खड़ी एक महिला भी कर्मचारी से बहस करती है। वीडियो बना रहा आदमी कहता है कि वह कर्मचारी की दिखावा कि वह क्या कर सकता है। एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए एक अन्य वीडियो में, आदमी बस स्टॉप पर बने टिकट ऑफिस में जाता है। वह कर्मचारियों से पूछता है कि क्या महिलाओं के लिए

मारा मुक्का अगले दिन का एक और वीडियो सामने आया। इसमें दिखता है कि कुछ लोग पब्लिक टॉयलेट में एक कर्मचारी को घेरे हुए हैं। उनमें से एक आदमी उसे चेहरे पर मुक्का मारता है।

एक दूसरा आदमी बीच-बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग कर्मचारी को तीन बार थप्पड़ मारते हैं। व पृष्ठते हैं कि तुम महिलाओं को गाली दे रहे हो ? क्या तुम मराठी में बात करोगे या नहीं ? क्या तुम्हें मराठी आती है ? एमएनएस के स्काफ पहनकर गुंडागर्दीएक आदमी कहता है, 'तुम्हें मराठी नहीं आती ? अगर तुमने कहा होता कि तुम्हें भाषा नहीं आती और तुम सीख रहे हो, तो क्या हम वाही होते ?' कर्मचारी आदमी के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है। फिर उसे टॉयलेट से बाहर ले जाया जाता है।

पालघर जिले के संपूर्ण विकास के लिए सांसद हेमंत सावरा ने रेलमंत्री वैष्णव से मुलाकात की

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

पालघर जिले के विकास और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सांसद डॉ. हेमंत सावरा ने केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जिले के नागरिकों, व्यापारियों, छात्रों और औद्योगिक इकाइयों की लम्बे समय से लंबित मांगों को शामिल किया गया है। पश्चिम रेलवे द्वारा पूर्व में दो ट्रेनों के ठहराव को स्वीकृति मिलने पर रेल मंत्री के प्रति आभार जताया गया है, वहीं शेष दो ट्रेनों-बांद्रा-सुरत इंटरसिटी और बांद्रा-गाजीपुर एक्सप्रेस के लिए भी सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा की गई है। ज्ञापन में बांद्रा-उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम बदलकर श्री महाराणा प्रताप सुपरफास्ट एक्सप्रेस करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। सांसद ने तर्क दिया कि यह नाम आम जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सांसद डॉ. सावरा ने पालघर स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों- जैसे अगस्त क्रांति

तेजस राजधानी, अवैतिका सुपरफास्ट एक्सप्रेस और बांद्रा-उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की है। साथ ही जोधपुर-पुणे, दादर-अजमेर, बांद्रा- भावनगर और दौंड-इंदौर जैसी ट्रेनों के स्टॉप भी पालघर स्टेशन पर रखने का अनुरोध किया गया है। बोईसर और वसई रोड स्टेशन और के संबंध में ज्ञापन में विशेष मांगें रखी गई हैं- ट्रेनों के अधिकारम ठहराव की अनुमति, पालघर-डहानू रोड मेमू सेवा को बोईसर/नवापुर तक बढ़ाने, फ्लाईंग रानी एक्सप्रेस को उमरसादी में रुकवाने वसई-डहानू मेमू को बोईसर/उमरसादी तक विस्तार देने की मांग शामिल है। उल्लेखनीय है कि इन मांगों को लेकर बोईसर रोड से जुड़ी नौ ग्राम पंचायतें 2017 से प्रयासरत हैं। डॉ. सावरा ने कहा कि यदि ये मांगें पूरी होती हैं तो शिक्षा, व्यापार और संचार क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पालघर जिले के समग्र रेलवे विकास के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा और वे तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती।

पश्चिम रेलवे पर कर्मचारी संपर्क अभियान की शुरुआत

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता द्वारा पोस्टर जारी कर अभियान का शुभारंभ

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मुंबई, पश्चिम रेलवे अपने कर्मचारियों के कल्याण एवं खुशहाली के लिए सदैव अग्रणी रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता के तत्वावधान और कुशल मार्गदर्शन में पश्चिम रेलवे के सभी छह मंडलों में एक अनूठी पहल रकमचारी संपर्क अभियान शुरू की गई है। इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता, पश्चिम रेलवे के अप्रम महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्रीमती मंजुला सक्सेना और पश्चिम रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 24 जुलाई, 2025 को कर्मचारी संपर्क अभियान पोस्टर जारी किया गया। ये पोस्टर चार भाषाओं, अर्थात हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, जिन्हें कर्मचारियों के साथ समावेशिता



और प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों में प्रदर्शित किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य कर्मचारियों के कल्याण, समय पर शिकायत निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस

अभियान के माध्यम से ट्रैकमैन/गैंगमैन जैसे फील्ड स्टाफ तक पहुंचने पर विशेष जोर दिया गया है, जो लगातार ड्यूटी पर रहते हैं और अक्सर समय पर अपनी समस्याएं व्यक्त नहीं कर पाते। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करना और उनके कल्याण से जुड़े मामलों को एक सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीके से निपटान करना है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका	
ई-निविदा सूचना	
निविदा दस्तावेज क्र.	बोली क्र. 2025_एमसीजीएम_1203366_1
संगठन का नाम	टीबी अस्पताल समूह, शिवडी
विषय	जीटीबी अस्पताल, शिवडी में 02 बॉइलर्स और 01 स्टर्लाइजर हेतु वार्षिक अनुक्षण ठेका (एमएस)
निविदा का शुल्क	1452 + (18.0% जीएसटी)
ई-निविदा का शुल्क (अनुमानित लागत)	आइटम दर निविदा
बोली सुरक्षा जमा/ईएमडी	रु. 6,200.00
निविदा जारी करने तथा बिड्डी की तिथि	25.07.2025 को 11.00 बजे से
बोली सुरक्षा जमा की स्वीकृति तथा निविदा की बिड्डी की अंतिम तिथि एवं समय	31.07.2025 को 12.00 बजे तक
लिफाफा ए और लिफाफा बी का खुलना	02.08.2025 को 14.00 बजे के पश्चात
पत्राचार हेतु पता	कार्यालय :- चिकित्सा अधीक्षक, जीटीबी अस्पताल, जेरबाई वाडिया रोड, शिवडी, मुंबई – 400 015
बोली खुलने का स्थान	चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में ऑनलाइन
हस्ता./-	
पीआरओ/1112/विज्ञा./2025-26	
चिकित्सा अधीक्षक, जीटीबीएच	
आइये एकजुट होकर मुंबई को मलेरिया मुक्त करायें.	



अनाधिकृत इमारतों की जलापूर्ति तत्काल बंद करें : मनपा आयुक्त

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

ठाणे, मनपा क्षेत्र के मौजे शील में अनाधिकृत निमाणों को जलापूर्ति के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव को अनाधिकृत निमाणों को जलापूर्ति के संबंध में जाँच करने का आदेश दिया है। इस मुद्दे पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बैठक बुलाकर अनाधिकृत इमारतों की जलापूर्ति तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूपन मामले हेतु आज आयुक्त कक्ष में जल आपूर्ति विभाग के संबंधित अधिकारियों की तत्काल एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर आयुक्त 2 प्रशांत रोडे, उपायुक्त (मुख्यालय) जी. जी. गोदेपुरे, उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) शंकर पटोले, विधि अधिकारी मकरंद काले, उपनगर अभियंता विनोद पवार, सहायक आयुक्त और जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कहा गया कि यदि अनाधिकृत निमाणों को जलापूर्ति प्रदान की गई है, तो उसके दस्तावेजों की जाँच की जाए और यदि निर्माण अवैध है, तो पाइप कनेक्शन तुरंत समाप्त किया जाए। इसी प्रकार, यदि मनपा को पाइप लाइन से अवैध रूप से पाइप कनेक्शन लिया गया है, तो उसे तुरंत समाप्त किया जाए। साथ ही, जल कनेक्शन प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि मनपा की निर्माण अनुमति के बिना किसी भी अनाधिकृत निर्माण को पाइप कनेक्शन न दिया जाए। साथ ही, आयुक्त ने पूर्व में दिए गए पाइप कनेक्शन तुरंत समाप्त करने के भी संबंधितों को आदेश दिए। आयुक्त सौरभ राव ने यह भी संकेत दिया कि यदि दस्तावेजों की जाँच किए बिना अनाधिकृत निमाणों को जल कनेक्शन दिए गए हैं, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त सौरभ राव ने निर्देश दिया कि ठाणे मनपा के 9 वार्ड समिति क्षेत्रों में अनाधिकृत इमारतों को अनुमति सहित और बिना अनुमति के दिए गए जल आपूर्ति कनेक्शनों की सूची तैयार की जाए और तदनुसार दिए गए सभी जल आपूर्ति कनेक्शन काट दिए जाएँ और अनाधिकृत बोरवेल के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।

जिला परिषद स्कूल में मेधावी छात्रों का किया गया सम्मान

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

ठाणे, किन्हावली बीट में छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों का जिला परिषद स्कूल, असनोली में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस विशेष अवसर पर, रोहन घुगे ने छात्रों से बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया। विशेष रूप से, उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, जो छात्रों के लिए एक अनूठा और यादगार क्षण बन गया। उनकी आत्मीयता से छात्र, शिक्षक और अभिभावक भावुक हो गए। छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और उन्हें पुस्तकें भेंट की गईं। इसी प्रकार, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों का भी जिला परिषद द्वारा विशेष रूप से सम्मान किया गया। इससे शिक्षण कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ इस अवसर पर



परियोजना निदेशक छायादेवी शिसोदे, शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) बालासाहेब राक्षे, संकुल विकास अधिकारी बाबू राठौड़, संकुल शिक्षा अधिकारी रामचंद्र विशेषे, विस्तार अधिकारी संगीता माली, केंद्र प्रमुख डॉ. राजेंद्र चौधरी (अल्हानी) पंचायत समिति अधिकारी, स्थानीय जन्मप्रतिनिधि, शाला प्रबंधन समिति के सदस्य, अभिभावक और विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नवनीत फरडे ने किया, परिचयात्मक भाषण राजेंद्र सापले ने दिया और

दूरस्थ आदिवासी गाँवों का जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे ने किया दौरा

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

ठाणे, जिला परिषद के अंतर्गत शाहपुर तालुका के दूरस्थ क्षेत्रों में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की परियोजना निदेशक छायादेवी सिसोदे और समूह विकास अधिकारी (शाहपुर) बी. एच. राठौड़ ने ग्राम पंचायत अजनुप के दापुर माल और खोरगादेवी आदिवासी गाँवों का प्रत्यक्ष दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। दूरस्थ के इन गाँवों तक पहुँचने के लिए कोई सड़क उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत माल से स्थानीय लोगों को 5 किलोमीटर की पथरीली और कीचड़ भरी सड़क पार करके पैदल यात्रा करनी पड़ती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने निर्देश दिए कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच 11 घरकुल स्वीकृत किए गए हैं और वर्ष 2024-25 में 22 घरकुल शुरू किए जाएँ और घरकुलों का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इसके अलावा, इस एस्टेट पर एक आंगनवाड़ी और एक जिला



परिषद स्कूल है, लेकिन भवन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री न मिल पाने के कारण, उन सरकारी इमारतों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। इस पृष्ठभूमि में, घुगे ने ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। इस अवसर पर उन्होंने घरकुलों के निर्माण के लिए सीएसआर निधि से विशेष सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। पानी की सुविधा के अभाव के कारण, अजनुप गाँव से

दो चरणों में लिफ्टिंग के माध्यम से जलापूर्ति योजना तैयार की जाएगी, और उन्होंने संबंधित जल आपूर्ति अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शाहपुर के गट शिक्षा अधिकारी को जिला परिषद स्कूल भवन के निर्माण के लिए तुरंत प्रस्ताव प्रस्तुत करने और कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। महल तक सड़क न होने के कारण होने वाली भारी असुविधा को देखते

स्कूल-कॉलेज क्षेत्रों में पान की टपरियों पर ई-सिगरेट बेचने वालों अंकुश लगाने की मांग

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

ठाणे , मीरा-भायंदर शहर में स्कूल-कॉलेजों के छात्र बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक सिगरेट का इस्तेमाल करते देखे जा रहे हैं। शिवसेना नेता और पूर्व सांसद राजन विचारे ने मीरा-भायंदर के नवनिवृत्त पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक को बधाई दी और एक पत्र के माध्यम से मांग की कि मीरा-भायंदर शहर के स्कूल-कॉलेज क्षेत्रों में पान की टपरियों पर इलेक्ट्रिक सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजन विचारे ने यह भी मांग की है कि पान की टपरियों पर ई-सिगरेट बेचने वालों को पुलिस की वर्दी दिखाई जाए। इस अवसर पर संपर्क प्रमुख नरेश मनैरा, मीरा-भायंदर जिला प्रमुख प्रभावकर म्हात्रे, उप जिला प्रमुख मनोज मयेकर, महिला मोर्चा की नीलम धवन, प्रकाश जैन आदि उपस्थित थे। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि मीरा-भायंदर शहर में बढ़ती जनसंख्या के कारण कई अनाधिकृत स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं और कक्षाओं की संख्या भी उसी के अनुसार बढ़ गई है। प्रशासन का नियंत्रण खत्म होने के कारण शिक्षकों ने बच्चों को अनुशासन सिखाने में लापरवाही बरती है। पहले अब कक्षा पाँचवीं से सातवीं तक बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। वर्तमान में, जैसे-जैसे बच्चों के वयस्क होने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, बच्चों में सोशल मीडिया को मदद से यौन इच्छाएँ जगाने, शराब पीने, गांजा पीने और सिगरेट पीने की



प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। साथ ही, पान की दुकानों पर अलग-अलग फ्लेवर में नई इलेक्ट्रिक सिगरेट बेची जा रही हैं। और इसकी शुरुआत सिगरेट और गांजे से हो रही है, इसलिए साइकिल पर पान बेचने वालों पर कार्रवाई करें और उन्हें जेल भेजें। साथ ही, स्कूल और कॉलेज परिसर में पुलिस का डर नहीं होना चाहिए और अगर कोई छात्र नशे में देखा गया तो स्कूल को छवि खराब होगी। शिवसेना नेता और पूर्व सांसद राजन विचारे ने मांग की है कि बच्चे को उसके माता-पिता को सौंप दिया जाए और उन्हें उचित समझ दी जाए। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस संबंध में ठाणे और नवी मुंबई के पुलिस आयुक्तों से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग गुटखा के अलावा किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। सरकार को इसके लिए नीति बनाकर इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मिर्जापुर, राजगढ़ पशु चिकित्सालय एवं पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं में होने वाली खुरपका-मुंहपका रोग के नियंत्रण के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत गो आश्रय स्थल नदिहार, गो आश्रय स्थल धनसिरिया एवं करौदा में पशुओं का टीकाकरण किया गया है। राजगढ़ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अग्रेश यादव ने बताया कि इस अभियान में पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही सुअर पालकों का संवेदीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें सुअर पालकों को साफ-सफाई के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्हें सुअर पालन स्थल को साफ-सुथरा रखने की सलाह दी जा रही है। साफ-सफाई न होने पर मस्तिष्क ज्वर होने का खतरा बना रहता है। डॉ. यादव ने बताया कि बरसात के मौसम में पशुपालकों को अपने पशुओं को साफ-सुथरा रखना चाहिए और टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। खुरपका-मुंहपका रोग होने से पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कक्षा 10 के छात्रों के बीच बैठने को लेकर मारपीट दो दिन में दो बार हुई झड़प, दोनों छात्रों को स्कूल से निकाला

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मिर्जापुर, संतनगर थाना क्षेत्र के महावीर प्रसाद मेमोरीयल इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के दो छात्रों के बीच बेंच पर बैठने को लेकर विवाद हुआ। मंगलवार को पहली बार हुई मारपीट के बाद मामला संतनगर थाने तक पहुंचा। वहां दोनों पक्षों के परिजनों ने आपस में समझौता कर लिया। बृहस्पतिवार को दोनों छात्र फिर विद्यालय पहुंचे और उसी मुद्दे पर पुनः विवाद हो गया। इस बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक-दूसरे के साथ मारपीट की। छात्र धर्मेन्द्र पाल ने बताया कि विपक्षी छात्र अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला किया, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा। इसके बाद वह पटेहरा पीएचसी पहुंचा। विद्यालय प्राचार्य भोला यादव ने बताया कि मंगलवार को पहली घटना के बाद दोनों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया गया था। लेकिन छुट्टी के बाद



धर्मेन्द्र पाल और विकास के बीच स्कूल के बाहर फिर झगड़ा हुआ, जिसमें विकास का सर फट गया था। इस मामले में भी थाने पर समझौता हो गया था। बृहस्पतिवार को उसी बात पर छींटकशी के कारण दोनों छात्र फिर भिड़ गए।

घर में घुसी कार, एक की मौत हादसे में एक घायल, चालक फरार; ग्रामीणों ने किया सड़क जाम



मिजापुर, जमुई में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घर में जा घुसी। हादसा जमुई अंडरपास से कालिका मूर्ति मार्ग पर हुआ। टक्कर के दौरान घर में मौजूद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल ट्रामा सेंटर भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार बहुत तेज गति में थी और चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभाला और जाम हटवाया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

स्कूल मर्जर के विरोध में सपा महिला सभा का प्रदर्शन

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

शाहजहांपुर, सरकार के स्कूल मर्जर फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी महिला सभा ने विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष विद्यालय के नेतृत्व में कार्यकर्ता खिरनीबाग रामलीला मैदान में एकत्र हुए। वहां से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। महिला सभा ने जिला प्रशासन को जापन सौंपा। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया रोकने की मांग की गई। साथ ही रसोइयों की पुनर्बहाली, उन्हें सम्मानजनक मानदेय के मांग की गई। सपा-सफाई न होने पर मस्तिष्क ज्वर होने का खतरा बना रहता है। डॉ. यादव ने बताया कि बरसात के मौसम में पशुपालकों को अपने पशुओं को साफ-सुथरा रखना चाहिए और टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। खुरपका-मुंहपका रोग होने से पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।



विद्यालय और तीन किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। उनका कहना है कि स्कूल मर्जर से ग्रामी बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने बताया कि विलय के बाद कई बच्चों को दूर के स्कूलों में जाना पड़ रहा है।

इस वजह से वे शिक्षा छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार विरोध और बच्चों की गुहार के बावजूद सरकार अपना फैसला नहीं बदल रही है। महिला सभा ने मांगें न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

फर्जी जांच कर कांवड़ियों से वसूली

डीजे परमिशन चेक के नाम पर 500 रुपये मांग रहे थे, तीन आरोपी पकड़े गए

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

शाहजहांपुर, कांवड़ यात्रा के दौरान फर्जी तरीके से डीजे परमिशन चेक करने का मामला सामने आया है। थाना कांट क्षेत्र के बलीपुर गांव के पास चार युवक कांवड़ियों से डीजे की परमिशन मांग रहे थे। परमिशन न होने पर वे 500 रुपये की रसीद काटने की कोशिश कर रहे थे। युवकों के गले में आईकाई लटका था। वे खुद को सरकारी कर्मचारी बता रहे थे। कांवड़ियों और स्थानीय ग्रामीणों ने जब उनसे आईकाई और परमिशन के बारे में पूछा, तो वे सही जवाब नहीं दे पाए। इस दौरान एक युवक को सभासद बताया जा रहा है वह मौके से फरार हो गया। कान पकड़कर मांगी माफी आक्रोशित लोगों ने तीन युवकों को



हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि तहरीर मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की लापरवाही को भी दर्शाती है। शासन के निर्देश पर पुलिस दिन-रात ड्यूटी कर रही है, लेकिन इन फर्जी जांचकर्ताओं को पकड़ने में स्थानीय लोगों की मदद लेनी पड़ी।

भारत संवाद परिवार

1-संरक्षक-भारत संवाद डॉ राम किशोर शर्मा पूर्व विभागाध्यक्ष इलाहाबाद विश्व विद्यालय कबीर सम्मान 2021 से सम्मानित, 2-संरक्षक-भारत संवाद आचार्य पं० पृथ्वीनाथ पाण्डेय भाषाविज्ञानी एवं मीडियाध्ययन विशेषज्ञ 3-संरक्षक-भारत संवाद गजानन महतपुरकर (सुपरिचित कवि, लेखक, गीतकार, मंच संचालक, स्वतंत्र पत्रकार एवं सदस्य, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी तथा पश्चिम रेलवे, चर्चगेट के वरिष्ठ जनसमर्पक अधिकारी पद से सेवानिवृत्त) 4-कला एवं मनोरंजन संपादक (भारत संवाद) जगन्नाथ तिवारी 5-उपसंपादक (भारत संवाद) माता प्रसाद शर्मा 6-प्रभारी प्रयागराज संस्करण (भारत संवाद) आशीष कुमार शर्मा

कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 12 थाई लोगों की मौत

थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, एफ-16 तैनात किया

एजेंसी

बैंकॉक, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज सुबह सीमा पर गोलाबारी हुई है। कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 12 थाई लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 14 घायल हैं। थाईलैंड ने जवाब में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि थाई सैनिकों ने सुबह गोलीबारी की,

जबकि थाई सेना ने कहा कि कंबोडिया ने पहले ड्रोन से हमला किया और फिर तोप और लंबी दूरी के बी.एम.21 रॉकेटों से हमला किया। हमले को देखते हुए थाईलैंड ने बॉर्डर पर एफ-16 लड़ाकू विमान तैनात किया है। इस साल 28 मई को बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। इसी विवाद की वजह से इंडोनेशिया की पीएम पाइतोनान शिनवात्रा को भी पद से हटाया गया था।



हमले के बाद थाईलैंड ने सीमा से लगे

86 गांवों से लगभग 40 हजार नागरिकों

को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। वहीं, कंबोडिया में रहने वाले थाई लोगों को भी अपने देश लौटने की अपील की गई है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह स्थित रॉयल थाईलैंड दूतावास ने कहा कि सीमा पर स्थिति बिगड़ती जा रही है और झड़पों के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना के कारण, दूतावास ने अपने नागरिकों से जितनी जल्दी हो सके कंबोडिया छोड़ने को कहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद का इतिहास 118 साल पुराना है, जो प्रीह विहार मंदिर

और आसपास के क्षेत्रों को लेकर है। जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था तभी 1907 में दोनों देशों के बीच 817 किमी की लंबी सीमा खींची गई थी। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया, क्योंकि नक्शे में प्रीह विहियर नाम का ऐतिहासिक मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। इस पर दोनों देशों में विवाद चलता रहा। 1959 में कंबोडिया यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले गया और 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया

लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जारी रहा। 2008 में यह विवाद तब और बढ़ गया जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की कोशिश की। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में फिर झड़पें शुरू हो गईं और 2011 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। 2011 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दोनों देशों को विवादित क्षेत्र से सैनिक हटाने का आदेश दिया, और 2013 में फिर से पुष्टि की कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र कंबोडिया का है। लेकिन सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह हल नहीं हो

पाया है। इस विवाद के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी देशों में से माने जाते थे। कुछ साल पहले तक दोनों देशों के नेताओं का मानना था कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि वे एक लंबी सीमा साझा करते हैं और मिलकर आगे बढ़ना उनके लिए जरूरी है। लेकिन हाल के समय में हालात बदल गए और उनके बीच तनाव काफी बढ़ गया है। 28 मई को एमराल्ड ट्रायंगल पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। यह वो जगह है थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं।

मोदी को मालदीव दौरे से पहले वहां आतंकी बताया गया

राष्ट्रपति के साले ने लिखा- मोदी आतंकी, इस्लाम के दुश्मन; फिर पोस्ट डिलीट की

एजेंसी

माले, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु के साले और सलफी जमीयत के नेता शेख अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद इब्राहिम ने पीएम मोदी को आतंकवादी कहा और उन पर बाबरी मस्जिद तोड़ने का आरोप लगाया है। मालदीव के अखबार अधाधु की रिपोर्ट के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद अब्दुल्लाह ने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी। फिलहाल मालदीव सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। पीएम मोदी 25 जुलाई को मालदीव के दौर पर जाने वाले हैं। यहां वे 26



जुलाई को होने वाले मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल

होंगे। शेख अब्दुल्लाह ने एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा था- मोदी इस्लाम

के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वे आतंकवादी हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई है, पुरानी मुस्लिम जमीनों को लूटा और अहमदाबाद को कब्रिस्तान में बदल दिया। उन्हें मालदीव बुलाना बड़ी गलती है। शेख अब्दुल्लाह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु की पत्नी साजिदा मोहम्मद की ओर से बनाए गए एक संगठन से जुड़ा है। पीएम मोदी 25 जुलाई को मालदीव पहुंचेंगे। 26 जुलाई को वहां के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान वे द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यह मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच व्यापार, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों

पर सहयोग को मजबूत करेगी। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जु के साथ अक्टूबर 2024 में हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर काम शुरू किया है। मोहम्मद मुइज्जु के साले के उलट मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि अगर भारत नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। नशीद ने एएनआई से बातचीत में कहा कि उनके देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अगर भारत ने समय पर मदद न की होती, तो मालदीव दिवालिया (डिफॉल्टर) हो गया होता।

सीरिया में इदलिब शहर के बारूद डिपो में विस्फोट

2 की मौत, 71 से ज्यादा घायल; धमाके की वजह साफ नहीं

एजेंसी

दमिश्क, सीरिया के उत्तर-पश्चिमी शहर इदलिब में गुरुवार को एक गोला-बारूद डिपो में विस्फोट की वजह से 2 लोग मारे गए हैं, जबकि 71 घायल हुए हैं। पीड़ितों की गिनती अभी भी जारी है। लोकल लोगों ने मीडिया को बताया कि इदलिब के उत्तर में मरात मिसरिन करबे में यह



की है। कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी है। अभी तक विस्फोट की वजह का पता नहीं चल सका है। इदलिब सीरिया के उत्तर-पश्चिम में है। यह हमा, अलेप्पो और लताकिया राज्य से घिरा है। इदलिब, अलेप्पो और दमिश्क को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है, जिस वजह से यह मिलिट्री और व्यापारिक नजरिए

से खास है। इदलिब में लगभग 45 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 19 लाख रिफ्यूजी कैम्प में रहते हैं। गृहयुद्ध और 2023 के भूकंप की वजह से इस इलाके में गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इदलिब लंबे वक्त से आतंरिक अशांति से जूझ रहा है। पिछले साल विद्रोही गुट में हयात तहरीर अल-शम (एचटीएस) और उसके सहयोगी ने सीरिया की तत्कालीन बशर अल असद की सरकार को हटाकर इस शहर पर कब्जा कर लिया था।

दक्षिण कन्नड़ जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी स्कूल और कॉलेज में अवकाश घोषित



एजेंसी

कर्नाटक के तीन तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ में 23 जुलाई की रात से भारी बारिश दर्ज की गई है। राज्य में मानसूनी बारिश फिर से तेज होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले सप्ताह कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। कर्नाटक में, उडुपी, उत्तर कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक जिलों में अत्यधिक वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने गोवा के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और बारिश के रेड अलर्ट के मद्देनजर दक्षिण कन्नड़ (डीके) जिले के कुछ हिस्सों में अवकाश घोषित कर दिया गया। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। के मद्देनजर लिया गया है जिसमें दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया कि सुलिया और बेलथांगडी तालुकों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को आंगनबाड़ियों, प्राथमिक व उच्च विद्यालयों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अवकाश घोषित किया जाता है इसके अलावा, मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। तहसील स्तर के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से मुख्यालय में रहने के लिए कहा गया है। इस वर्ष दक्षिण कन्नड़ जिले में अब तक 3,026 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जो सामान्य बारिश के आंकड़े 2,091 मिलीमीटर से लगभग डेढ़गुना है पिछले चौबीस घंटे में दक्षिण कन्नड़ जिले में 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है। दक्षिण कन्नड़ जिले में इस वर्ष मानसून मौसम में अब तक वर्षाजनित घटनाओं में छह लोगों की मौत हो चुकी है।

कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और बारिश के रेड अलर्ट के मद्देनजर दक्षिण कन्नड़ (डीके) जिले के कुछ हिस्सों में अवकाश घोषित कर दिया गया। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। दक्षिण कन्नड़ जिले में इस वर्ष मानसून मौसम में अब तक वर्षाजनित घटनाओं में छह लोगों की मौत हो चुकी है।

एसआईआर पर एनएसयूआई का पटना में बवाल

विरोध प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने बढ़ती बेरोजगारी पर जवाब न दे पाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य अराजकता और अराजकता की स्थिति में पहुँच गया है।

एजेंसी

कांग्रेस से संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को चुनावी राज्य बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद, पटना में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स हटाने की कोशिश करने पर कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछोरें की गईं और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। विरोध प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने बढ़ती

पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, कांग्रेस का केंद्र पर निशाना



बेरोजगारी पर जवाब न दे पाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य अराजकता और अराजकता की स्थिति में पहुँच गया है। कांग्रेस नेता ने एएनआई को बताया कि युवा नौकरी और रोजगार की माँग कर रहे हैं और पलायन के खिलाफ हैं। बिहार में अराजकता और अराजकता का माहौल है। सरकार जवाब और स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है, इसलिए अब कांग्रेस के पास विरोध प्रदर्शन के

अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। धरना स्थल पर मौजूद पटना के अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट - कानून व्यवस्था (एडीएम) गोविंद पांडे ने कहा कि सड़क को साफ करना होगा, अन्यथा स्कूल बसों रोक दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन के कारण एक एम्बुलेंस पहले से ही पीछे फँसी हुई है। पटना के एडीएम ने एएनआई को बताया कि इलाका ऐसा है कि स्कूल बसों के आने का समय हो गया है, लेकिन कोई अनुमति वगैरह नहीं है। हमें सड़क खाली करानी है,

स्कूल बसों और एक एम्बुलेंस पीछे से रुकी हुई हैं, अगर आप देखें तो... सभी को हिरासत में लिया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान, एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को धक्का देते और उन पर चढ़ने की कोशिश करते देखे गए, जबकि उन पर पानी की बौछोरें की जा रही थीं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच, अधिकारियों ने बैरिकेड्स को नीचे गिरा दिया और उन सभी अधिकृत प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की जो बैरिकेड्स तोड़कर मौके पर धरना देने में कामयाब रहे। इससे पहले आज, राज्य के विपक्षी नेताओं ने इस साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआर) द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

शिकायत में आरोप लगाया गया कि संजय भारती ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए अभद्र का प्रयोग किया था और धमकी दी थी।

एजेंसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चित्तबड़गांव मंडल के अध्यक्ष मोती चंद्र गुप्त की तहरीर पर चित्तबड़गांव थाना क्षेत्र के पलियारा गांव निवासी संजय भारती के विरुद्ध



भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संजय भारती ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए अभद्र का प्रयोग किया था और धमकी दी थी। अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि पुलिस ने आरोपी संजय भारती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

क्या आपने उन्हें कभी गंभीर राजनीति करते देखा है? : निशिकांत दुबे

निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर कोई सदस्य बोलना चाहता है, तो उसे सदन में बैठना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने नियम नहीं पढ़े हैं। उन्हें सीखना चाहिए कि सरकार कैसे काम करती है, और उन्हें यह मल्लिकार्जुन खड़गे से सीखना चाहिए, अगर किसी और से नहीं।

एजेंसी

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तगड़ा वार

राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे का वार

किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के इतिहास में एकमात्र ऐसे विपक्ष के नेता हैं, जिन्हें देश के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। क्या आपने उन्हें कभी गंभीर राजनीति करते देखा है? दुबे ने आगे कहा कि वह मुश्किल से दो मिनट के लिए मीडिया के सामने आते हैं। कई सत्रों में उनकी उपस्थिति शून्य रही है। संसद के कुछ नियम और आचार संहिताएँ होती हैं। नियम 349 के अनुसार, कोई भी सदस्य सदन में बोलने के तुरंत बाद सदन नहीं छोड़

सकता। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर कोई सदस्य बोलना चाहता है, तो उसे सदन में बैठना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने नियम नहीं पढ़े हैं। उन्हें सीखना चाहिए कि सरकार कैसे काम करती है, और उन्हें यह मल्लिकार्जुन खड़गे से सीखना चाहिए, अगर किसी और से नहीं। प्रोविजन्सल रिपोर्ट कहती है कि अंतर्प्रेषण सिंदूर में हमारी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि स्थाई रिपोर्ट तब बनेगी जब हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे।



एसआईआर पर उनका बयान दर्शाता है कि उन्हें अपने पिता द्वारा पारित कानून की जानकारी नहीं है। 12003 में भी ऐसा ही एसआईआर किया गया था। इससे

पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की

अनुमति है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जो विपक्ष का नेता हूँ, को बोलने की अनुमति नहीं है। यह एक नया दृष्टिकोण है। परंपरा कहती है कि यदि सरकार की ओर से लोग बोल सकते हैं, तो हमें भी बोलने की जगह दी जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा कि अगर वे (सरकार) चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उन्हें विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए। वह बोलने के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोच्च है।

संक्षेप

बिजली कटौती से परेशान लोग

शहर में रात में ट्रिपिंग, गांवों में सिर्फ 6-7 घंटे आपूर्ति, एसी बोले-बारिश नहीं होने से आ रही समस्या

सुलतानपुर, विद्युत आपूर्ति की स्थिति गंभीर हो गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में दरियापुर फीडर से जुड़े इलाकों में रात होते ही बिजली ट्रिप होने की समस्या शुरू हो जाती है। यह समस्या रात 2-3 बजे तक जारी रहती है। डाकखाना, टाटियानगर और केएनआई फीडर की स्थिति भी खराब है। कूरेभार ब्लॉक में गलिवहा समेत चार उपकेंद्रों की स्थिति चिंताजनक है। इन उपकेंद्रों से जुड़े करीब 50 गांवों में पिछले 15 दिनों से केवल 6-7 घंटे ही बिजली मिल रही है। इससे एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। भदैया ब्लॉक में एक महीने से लो वोल्टेज की समस्या है। यहां 10-12 घंटे की सीमित आपूर्ति होती है। पकड़ी उपकेंद्र के बालमपुर फीडर पर पांच घंटे तक बिजली बंद रही। इससे 25 गांवों की आपूर्ति प्रभावित हुई। लोलेपुर उपकेंद्र के ईस्ट कीडर पर तीन दिनों से रात 9 बजे से सुबह 2 बजे तक बिजली नहीं रहती। कुड़वार और असरोगा पावर हाउस की स्थिति सबसे खराब है। इनके अंतर्गत आने वाले दाऊदपुर, बंधुआकला, धंमौर व कुड़वार फीडर पर 24 घंटे में केवल 3-4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है।

स्कूल विलय से बच्चों की पढ़ाई पर असर

असवा धनीपुर स्कूल का नौबस्ता में विलय, तालाब की दूरी से 7 बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई

सुलतानपुर, भदैया में परिषदीय विद्यालयों के विलय की नीति बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। असवा धनीपुर प्राइमरी स्कूल का नौबस्ता प्राइमरी स्कूल में विलय कर दिया गया है। इस विलय के बाद असवा धनीपुर स्कूल पर ताला लगा गया है। असवा धनीपुर स्कूल में पहले 28 बच्चे पढ़ते थे। विलय के बाद रास्ते में तालाब आने के कारण सात बच्चों ने निजी स्कूलों में दाखिला ले लिया है। नौबस्ता स्कूल में पहले से ही 50 बच्चे पढ़ रहे थे। विलय के बाद कुल संख्या 78 होनी थी। लेकिन सात बच्चों के चले जाने से यह घटकर 71 रह गई है। नौबस्ता स्कूल में पहले तीन शिक्षक और एक शिक्षा मित्र कार्यरत थे।

कावड़ियों का जल्था देवघर रवाना

कोड़ीपुर रेलवे स्टेशन पर चेयरमैन ने श्रद्धालुओं को किया विदा

सुलतानपुर, चांदा से सैकड़ों कावड़िये गुरुवार को बाबा बैजनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुए। कोड़ीपुर रेलवे स्टेशन पर रामगंज के चेयरमैन राकेश सिंह ने कावड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने सभी कावड़ियों को जलपान कराया और सकुशल यात्रा की मंगल कामना के साथ विदा किया। युवा टीम रामगंज सहित क्षेत्र के सैकड़ों कावड़ियों देशवासियों को जलपान कराया और राकेश सिंह ने स्वयं स्टेशन पहुंचकर उनकी सेवा और स्वागत किया।

कांग्रेस नेता पूनम पंडित ने किया कॉरिडोर का विरोध प्रदर्शन में हुई शामिल, कहा- सनातन की बात करने वाली सरकार ही मंदिरों को उजाड़ रही

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

मथुरा, बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए जाए गए अध्यादेश के विरोध में 57 दिन से चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता पूनम पंडित पहुंचे। कांग्रेस नेता ने यहां कॉरिडोर का विरोध करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा काशी में कॉरिडोर दिखने में सुंदर है पर वहां आम श्रद्धालु 6-6 घंटे तक दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे हैं। कॉरिडोर के

एआईएमआईएम का करणी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

असदउद्दीन औवैसी, इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी के बाद सड़क पर उतरे, सौंपा ज्ञापन

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रयागराज इकाई द्वारा आज एक अहम कदम उठाते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन करणी सेना के नेता ठाकुर योगेन्द्र सिंह राणा द्वारा सोशल मीडिया पर दिए गए एक वीडियो बयान के विरोध में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख व हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदउद्दीन औवैसी, विधायक अकबरउद्दीन औवैसी और महिला सांसद इकरा हसन के प्रति अभद्र व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। एआईएमआईएम प्रयागराज महानगर अध्यक्ष अफसर महमूद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और इस घटना पर गहरी आपत्ति जताई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि उक्त



वीडियो से समाज में वैमनस्य फैलाने, आपसी सौहार्द बिगाड़ने और माननीय सांसदों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जो कि न केवल निंदनीय है बल्कि कानूनन दंडनीय भी है। अफसर महमूद ने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि ऐसी

प्राइमरी शिक्षक से नाक रगड़वाने का मामला

मोस्ट कल्याण संस्थान ने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और शिक्षक की बहाली की मांग

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

सुलतानपुर, कंपोजिट विद्यालय समरथपुर में शिक्षक ओम प्रकाश के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर मोस्ट कल्याण संस्थान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मोस्ट ने गुरुवार को डीएम को सम्बोधित एक पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। जहां जिलाधिकारी से बेरिफ शिक्षा में विधि का शासन कायम करने की मांग की है। स्कूल की एक छात्रा ने कांवड़ में शामिल होने के लिए छुट्टी मांगी थी। शिक्षक ओम प्रकाश ने उसे स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाने की सलाह दी थी। इसके पांच दिन बाद 22 जुलाई को गांव के सैकड़ों लोग स्कूल परिसर में घुस आए। उन्होंने छात्रा द्वारा लगाए गए धार्मिक टिप्पणी के आरोप के बहाने शिक्षक को गालियां दीं, माफी मंगवाई और फर्श पर नाक रगड़वाई। मोस्ट के अनुसार, बेसिक शिक्षा



अधिकारी (बीएसए) ने शिक्षक को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्वाचित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। मोस्ट ने शिक्षक ओम प्रकाश को तत्काल बहाल करने, उनकी तैनाती किसी अन्य ब्लॉक में करने और स्कूल परिसर में घुसकर अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। संगठन ने बीएसए को प्राकृतिक न्याय और दोहरे दंड से

अजय राय बोले- यूपी में 'जंगल राज'

भाजपा नेता सड़कों पर दौड़ाकर गोली मार रहे, उन पर कब चलेगा बुलडोजर?

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में उन दो भाइयों से मिलने पहुंचे, जो प्रतापगढ़ में गोलीकांड के शिकार हुए थे। उन्होंने पीडित दोनों भाइयों अरुण मिश्रा और आदित्य मिश्रा का हालचाल लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों को खुलेआम दौड़ा-दौड़ाकर गोली मारी गई, लेकिन अभी तक किसी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में कानून का नहीं, बल्कि दबंगों और नेताओं का राज चल रहा है। इस हमले का मुख्य आरोपी बीजेपी से जुड़ा ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह है। पुलिस और प्रशासन उसकी राजनीतिक ताकत की वजह से हाथ डालने से डर रहे हैं। अजय राय ने सरकार पर तंज कसते



हुए पूछा कि जब आरोपी बीजेपी का है, तो उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? उन्होंने कहा कि अगर यही काम किसी और समुदाय का ईसान करता, तो अब तक या तो उसका एनकाउंटर हो गया होता या फिर बुलडोजर चल गया होता। मंत्री जी सिर्फ कैमरे के सामने अधिकारियों की लगाते हैं डांट ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पर भी अजय राय ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री सिर्फ कैमरे के सामने अफसरों को डांटने का ड्रामा करते हैं,

असल में जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने दावा किया कि जब मंत्री वृंदावन दर्शन करने पहुंचे, तो वहां के संतों ने उन्हें दर्शन तक नहीं करने दिया और वापस भेज दिया। अजय राय ने कहा कि अब जनता बीजेपी नेताओं को जगह-जगह से भगा रही है और सरकार की साख खत्म हो चुकी है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप भी लगाया और कहा कि खुद मंत्री भी इसमें शामिल हैं।

पुश्तैनी जमीनी विवाद

महिला से मारपीट और जान से मारने की धमकी, एसपी से लगाई न्याय की गुहार

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अमेठी जिला, एक महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम तिवारीपुर मंजरे करनाईपुर, थाना संग्रामपुर निवासी गीता तिवारी ने एसपी कार्यालय गौरिगंज पहुंचकर अपनी समस्या बताई। गीता का आरोप है कि विपक्षी उसकी पुश्तैनी भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पुश्तैनी भूमि का बटवारा पहले ही हो चुका है। इसके बावजूद गांव के कुछ लोग उसकी जमीन पर कब्जा करने

की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने उसके साथ मारपीट की है। उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। गीता ने पुलिस अधीक्षक से विपक्षियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस



अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने पीड़िता को जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट

2 लाख से ज्यादा लोगों की ई-केवाईसी नहीं, इस महीने के बाद कट सकता है राशन

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अमेठी जिला, जिला पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। जिन कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। जिले में 765 सरकारी राशन दुकानें हैं। इनसे 2.73 लाख पात्र गृहस्थी कार्डधारक और 69,867 अंत्योदय कार्डधारी राशन लेते हैं। पात्र गृहस्थी के हर सदस्य को 5 किलो और अंत्योदय कार्डधारी को 35 किलो राशन मिलता है। पूर्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 2 लाख से अधिक लाभार्थियों की ई-केवाईसी अधूरी है। जिला प्रशासन ने सभी कोटेशनों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकानों पर लाभार्थियों से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराएं। कोटेशनों को ई-पॉश मशीन दी गई है। लाभार्थी



राशन कार्ड लेकर कोटेदार के पास जा सकते हैं। समय से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश मशीन पर अंगुठा लगाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है और किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी

शशिकांत ने कहा कि राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिनका विवरण अपडेट नहीं होगा, उनका नाम लिस्ट से हटाया जाएगा। उन्होंने सभी लाभार्थियों से समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

विकास में अदाणी फाउंडेशन का योगदान

शिक्षा, स्वास्थ्य और सोलर विलेज से बदली तस्वीर, टीबी मरीजों को पोषण किट

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अमेठी, गांवों में मुफ्त बिजली की रोशनी है, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान है और महिलाओं को मिला है नया आत्मविश्वास। ये सब मुमकिन हुआ है अदाणी फाउंडेशन की सतत कोशिशों से, जो अमेठी को एक आदर्श और आत्मनिर्भर जिला बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अदाणी फाउंडेशन प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अमेठी में रमोडल सोलर विलेज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पहल का मकसद ग्रामीण इलाकों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि ऊर्जा के लिए उनकी निर्भरता खत्म हो सके। हाल ही में एक विशेष कार्यक्रम में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की



उपस्थिति में अदाणी फाउंडेशन ने अमेठी में 100 टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की। मरीजों को ना केवल पौष्टिक सामग्री दी गई, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी सलाह और जागरूकता भी दी गई कि कैसे इस बीमारी से सुरक्षित रहना है। अदाणी फाउंडेशन ने अमेठी

के 10 सरकारी स्कूलों में 'बाला' वॉल पेंटिंग्स बनवाई हैं। ये पेंटिंग्स बच्चों को चित्रों और रंगों के माध्यम से पढ़ाई का नया तरीका सिखा रही हैं। इन चित्रों के जरिए विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक ज्ञान को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। टिकरिया स्थित

अदाणी एससी सीमेंट प्लांट के आस-पास के 11 आंगनवाड़ी केंद्रों में टेबल-कुर्सियों का वितरण कर बच्चों के बैठने की सुविधा सुधारी गई है। फाउंडेशन का लक्ष्य इन केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहां स्वच्छ जल और बेहतर आधारभूत सुविधाएं हों। युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार मेले, प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के जरिए अदाणी फाउंडेशन ने आजीविका के अवसरों को बढ़ाया है। विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए उपकरण और ट्रेनिंग की व्यवस्था कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। गांवों में जल संरक्षण की पहल और बुनियादी ढांचे के विकास ने स्थानीय लोगों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव लाया है।

गोकशी के आरोपियों पर कार्रवाई

अलीगढ़ में 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, 2.20 करोड़ की संपत्ति जब्त

भारत संवाद न्यूज नेटवर्क

अलीगढ़, थाना बरला पुलिस ने एक महिला सहित 10 गोकशी के आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने इन आरोपियों की 2 करोड़ 20 लाख रुपये की अवैध संपत्ति भी जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार, आरोपी आदिल खान मेहदी हसन, मेहदी हसन पुत्र बुद्धा खान निवासी पिलखाना, मेहरूद्दीन पुत्र रहमान खान, फिरोज पुत्र रज्जू खान निवासी सत्रापुर थाना छर्दा, साहिल



पुत्र शमशेर खान निवासी नगला बादशाह थाना छर्दा, इसरार पुत्र यामीन खान निवासी नगला बादशाह, मुशीर पुत्र बुद्धा खान निवासी पिलखाना, मुफोद पुत्र बुद्धा खान निवासी पिलखाना

और एक महिला आसमा पत्नी मोहिद पिलखाना को बरला व अकराबाद के बॉर्डर पर काली नदी से गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों ने 4 जुलाई को थाना बरला क्षेत्र के कस्बा पिलखाना स्थित दुकान में गोमांस काटकर एक स्विफ्ट कार में बिक्री के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरला मोड़ पर इन आरोपियों से गोमांस बरामद किया था। इस संबंध में थाना बरला पर मुकदमा दर्ज किया गया था और 4 आरोपियों को उसी समय गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।